भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1855

28 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

बेघर लोगों की संख्या

1855. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बेघरी की स्थिति क्या है और बेघर लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) भीषण गर्मी, बरसात के मौसम और शीत लहर जैसे चरम मौसम की स्थिति के दौरान उन्हें अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बेघर आबादी के लिए मकान बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कुल कितना आबंटन किया गया है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क): भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 9.38 लाख बेघर लोग हैं।

(ख) से (घ): भूमि और कालोनीकरण राज्य के विषय हैं। आवासों/आवासीय स्थानों/रैन बसेरों का निर्माण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है, जिसमें वित्त की व्यवस्था भी शामिल है। ऐसे आवासीय स्थानों और उनके वित्तपोषण का ब्यौरा मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा प्रस्तावित रैन बसेरों के निर्माण और संचालन के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करके दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहा है ताकि बेघर लोगों को कठोर मौसम जैसे लू, बरसात और शीत लहर से बचाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, 2022 तक 'सबके लिए आवास' के विज़न के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, 25.06.2015 से बेघरों सहित सभी पात्र परिवारों/ लाभार्थियों के लिए आवासों के निर्माण हेतु प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, अब तक सभी शहरी क्षेत्रों में पीएमएवाई-यू के तहत 122 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 102 लाख से अधिक आवास निर्माणाधीन हैं और 61 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए /लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू के तहत अब तक कुल 2.03 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मंजूर की जा चुकी है।

*****